बाजार में गिरावट, सैंसेक्स 155 अंक लुढ़का और निफ्टी 11430 पर हुआ बंद

नई दिल्ली, 10 अगस्त (ए)।ग्लोबल बाजारों से मिले कमजोर संकेतों से कल शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में कल सैंसेक्स 155.14 अंक यानि 0.41 फीसदी गिरकर 37,869.23 पर और निफ्टी 41.20 अंक यानि 0.36 फीसदी गिरकर 11,429.50 पर बंद हुआ।

मिड-स्मॉलकैप शेयरों में बढ़त:मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में कल गिरावट देखने को मिली है। बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.93 फीसदी और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.87 फीसदी गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी का मिडकैप 100 इंडेक्स 0.52 फीसदी गिरकर बंद हुआ है।

बैंक निफ्टी में गिरावट:बैंकिंग, फार्मा, मेटल में गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 196 अंक गिरकर 28124 के स्तर पर बंद हुआ है। इसके अलावा निफ्टी फार्मा में 1.21 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.91 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

टॉप गेनर्स:आइशर मोटर्स, बीपीसीएल, एचपीसीएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, टीसीएस, आईटीसी ।

टॉप लूजर्स:एसबीआई, आइडिया, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, वेदांता, टाटा स्टील ।

रेरा लागू होने से घरों के पजेशन में 33प्रतिशत की बढ़ोतरी: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। रियल एस्टेट रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) लागू होने से घरों की डिलीवरी में 33 फीसदी इजाफा हुआ। नौ प्रमुख शहरों में इस साल जनवरी से जून के बीच बिल्डरों ने 1 लाख 93 हजार 61 फ्लैट्स का पजेशन दिया। पिछले साल इन महीनों के दौरान यह संख्या 1 लाख 44 हजार 654 यूनिट थी।

2019 के अंत तक सौंपे जाएंगे 8.6 लाख घर:रियल्टी पोर्टल प्रॉपटाइगर की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 के आखिर तक करीब 8.6 लाख घर ग्राहकों को सौंपे जाने हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नोएडा और पुणे शहरों में प्रॉपटाइगर ने सर्वे किया। नोएडा में ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे को भी शामिल किया गया। इसी तरह मुंबई में नवी मुंबई, ठाणे और गुरुग्राम में भिवाड़ी, धारुहेड़ा और सोहना को भी शामिल किया।

डिमांड बढ़ने की उम्मीद:इस साल जून तक अहमदाबाद में 13,380 और बेंगलुरु में 28,279 घर ग्राहकों को सौंपे गए। गुरुग्राम में 24,677 और हैदराबाद में 11,887 वहीं कोलकाता में 8,314 घरों का पजेशन दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेरा लागू होने क बाद बिल्डर्स नई स्कीम लॉन्च करने की बजाय पुराने प्रोजेक्ट पूरे करने पर फोकस कर रहे हैं, ताकि पेनल्टी न लगे। रेरा की वजह से घरों का पजेशन समय पर मिलने लगा है। यह इंडस्ट्री के लिए अच्छा साबित होगा। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और आने वाले फेस्टिवल सीजन में घरों की बिक्री में भी इजाफा हो सकता है।

वैश्विक रुख और कमजोर मांग से सोना लुढ़का, चांदी फीकी

नई दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। कमजोर वैश्विक रुख के बीच स्थानीय आभूषण कारोबारियों की मांग घटने से कल दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 40 रुपए गिरकर 30,520 रुपए प्रति दस ग्राम रह गया। सिक्का निर्माताओं और औद्योगिक इकाइयों का उठाव घटने से चांदी भी 75 रुपए लुढ़क कर 38,895 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही।

बाजार सूत्रों ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं और स्थानीय आभूषण कारोबारियों की कमजोर मांग के साथ वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख से कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट आई। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर में, सोना 0.33 प्रतिशत गिरकर 1,208.10 डॉलर प्रति औंस पर रहा और चांदी 0.88 प्रतिशत गिरकर 15.29 डॉलर प्रति औंस रही। राष्ट्रीय राजधानी में, 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना क्रमशः 40-40 रुपए गिरकर 30,520 रुपए और 30,370 रुपए प्रति दस ग्राम पर रहा। पिछले दो दिनों में सोना 25 रुपए गिरा था। हालांकि, आठ ग्राम वाली गिन्नी 24,600 रुपए प्रति इकाई पर ही टिकी रही।

सेबी को फोन कॉल टैप करने का अधिकार देने की सिफारिश

मुंबई, 10 अगस्त (ए)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक समिति ने सुझाव दिया है कि भेदिया कारोबार और धोखाधड़ी के दूसरे तरीकों से निपटने के लिए बाजार नियामक को टेलीफोन तथा दूसरे संचार माध्यमों को टैप करने का अधिकार मांगना चाहिए।

सेबी के पास अभी कॉल रिकॉर्ड का ब्योरा मांगने का अधिकार है। अगर समिति की सिफारिशों को लागू किया जाता है तो सेबी को कॉल सुनने का भी अधिकार मिल जाएगा। निष्पक्ष बाजार आचरण के बारे में पूर्व विधि सचिव टी के विश्वनाथन की अगुआई वाली इस समिति ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसे आज सार्वजनिक किया गया। समिति का कहना है कि सेबी को कॉल टैप करने का अधिकार मांगना चाहिए लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए संबंधित कानूनों में जरूरी संशोधन किए जाने चाहिए।

अलायंस लॉ के प्रबंध निदेशक आरएस लूना ने कहा कि पुलिस और सीबीआई जैसी संस्थाओं को पहले से ही इस तरह के अधिकार हैं। उन्होंने कहा, 'सफेदपोश अपराध भी गंभीर अपराधों के बराबर हैं। भेदिया कारोबार जैसे अपराधों को साबित करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता कि कुछ शर्तों के साथ सेबी को कॉल रिकॉर्ड करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

किसी बड़े अधिकारी को कॉल रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका गलत इस्तेमाल न हो।' हालांकि फिनसेक लॉ एडवाइजर्स के संस्थापक और सेबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक संदीप पारेख ने कहा, 'आप वित्तीय नियामकों को इस तरह का अधिकार नहीं दे सकते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है।' समिति ने यह सिफारिश ऐसे वक्त की है जब निजता को लेकर देश में चर्चा गरम है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में अपने फैसले में कहा था कि निजता मौलिक अधिकार है।

समिति ने बेनामी खातों, भेदिया कारोबार और धोखाधड़ी के दूसरे तरीकों से निपटने के लिए भी सुझाव दिए हैं। धोखाधड़ी के मामले से बेहतर ढंग से निपटने के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई है। समिति का कहना है कि धोखाधड़ी के नियम केवल मध्यवर्ती संस्थाओं (डिपॉजिटरी और ब्रोकर आदि) तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि उनके कर्मचारियों को भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए। समिति ने खातों में हेरफेर करने वालों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान का सुझाव दिया है।

भेदिया कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें दो अलग आचार संहिताएं बनाना शामिल है। इनमें से एक सूचीबद्ध कंपनियों के लिए होगी। दूसरी मध्यवर्ती संस्थाओं और संवेदनशील जानकारी को संभालने वाले लोगों के लिए मानक तय करेगी। समिति का कहना है कि कंपनियों को संवेदनशील जानकारी को संभालने वाले लोगों के करीबी रिश्तेदारों की जानकारी रखनी चाहिए।

रिजर्व बैंक से अंतरिम लाभांश का विकल्प खुला है: गर्ग

नई दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू वित्त वर्ष में सरकार को अंतरिम लाभांश का विकल्प अभी खुला है। इस बारे में फैसला इसी साल आगे हो सकता है। आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग ने आज यह बात कही। रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने कल जून, 2018 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए 50,000 करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान करने का फैसला किया था। रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष जुलाई से जून होता है। लाभांश के वितरण को स्पष्ट करते हुए गर्ग ने कहा, ''आप साल समाप्त होने के बाद लाभांश देते हैं। रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष 30 जून को समाप्त होता है। अब वे खातों को अंतिम रूप दे रहे हैं और उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का लाभांश घोषित किया है। 2017-18 में 10,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश मिला। 40,000 करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष में आएंगे। यह पूछे जाने पर क्या अंतरिम लाभांश की गुंजाइश है, गर्ग ने कहा कि यह विकल्प खुला हुआ है। गर्ग ने कहा, ''पिछले साल की तरह इस वर्ष भी अंतरिम लाभांश आ सकता है। इसकी समीक्षा संभवतः दिसंबर में हो सकती है।''

गरीबों को दाल में 15 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी देगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य सरकारों को कल्याणकारी योजनाओं के लिए करीब 35 लाख टन दलहन थोक बाजार मूल्य से 15 रुपए प्रति किलो सस्ती दरों पर जारी करने का फैसला किया। इसके तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को, 'पहले आओ-पहले पाओ' आधार पर थोक बाजार मूल्य पर 15 रुपए प्रति किलो की छूट के साथ, 34.88 लाख टन तुअर, चना, मसूर, मूंग और उड़द जारी करने की पेशकश की जाएगी। यह निर्णय एक बार के लिए है जो 12 महीने के लिए है पर यदि 34.88 लाख टन का स्टॉक इससे पहले खत्म हो जाता है तो योजना वहीं खत्म कर दी जाएगी

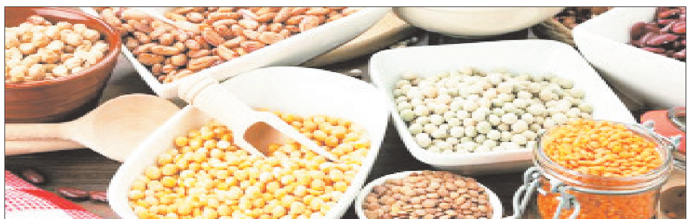

कानून और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 5,237 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह फैसला राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को गोदामों के लिए दाल उपलब्ध कराने के अलावा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में दालों का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे कि मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) में दालों का उपयोग करेंगे। देश में पिछले दो वर्षों से दालहनों के उत्पादन के नए रिकार्ड बन रहे हैं।

मूल्य समर्थन योजना के तहत केंद्र ने खरीफ 2017 और रबी 2018 विपणन सत्र के दौरान दालों की रिकॉर्ड खरीददारी की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत 45.43 लाख टन दालों की रिकॉर्ड खरीद की गई है। इसमें कहा गया है कि आने वाले खरीफ सत्र में, दालों का उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि इसके साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण मूल्य समर्थन योजना के तहत अतिरिक्त खरीद की आवश्यकता होगी।

आधार पर चैलेंज करने वाले ट्राई प्रमुख आरएस शर्मा का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा

नई दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के प्रमुख राम सेवक शर्मा का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया। ट्राई प्रमुख के कार्यकाल विस्तार संबंधी अपने आदेश में कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने ट्राई चेयरमैन के रूप में शर्मा की नियुक्ति को 10 अक्तूबर 2018 से आगे 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

2015 में बनाया गया था TRAI प्रमुख:शर्मा को जुलाई 2015 में तीन वर्ष के लिए ट्राई प्रमुख बनाया गया था। शर्मा 1982 बैच के झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। शर्मा हाल ही में ट्विटर पर अपनी आधार संख्या सार्वजनिक करने और लोगों को चुनौती देने को लेकर

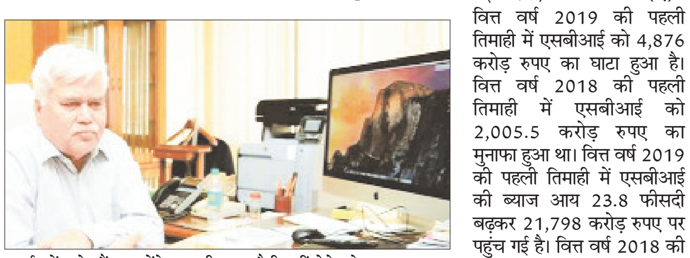

चर्चा में रहे हैं। उन्होंने अपनी आधार संख्या डालते हुए चुनौती दी थी कि इस जानकारी के आधार पर उन्हें नुकसान पहुंचाकर दिखाएं। शर्मा के इस कदम के बाद उनकी सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई थी। वहीं, आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने लोगों को आधार संख्या सार्वजनिक नहीं करने या दूसरे को इस तरह की चुनौती नहीं देने को कहा था।

आधार परियोजना लागू करने में निभाई अहम भूमिका:ट्राई प्रमुख बनाने से पहले शर्मा सूचना प्रौद्योगिकी सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। आधार परियोजना को लागू करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी।

वह यूआईडीएआई में महानिदेशक और मिशन निदेशक के पद पर भी रह चुके हैं।

एसबीआई को 4876 करोड़ रुपए का घाटा

नई दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही में एसबीआई को 4,876 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वित्त वर्ष 2018 की पहली तिमाही में एसबीआई को 2,005.5 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही में एसबीआई की ब्याज आय 23.8 फीसदी बढ़कर 21,798 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2018 की पहली तिमाही में एसबीआई की ब्याज आय 17,606 करोड़ रुपए रही थी।हालांकि जून तिमही के दौरान बैंक के फंसे हुए कर्ज (एनपीए) में कमी देखने को मिली है, एसबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जून तिमाही में उसका ग्रॉस एनपीए 2,12839.92 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, इससे पहले मार्च तिमाही में बैंक का ग्रॉस एनपीए 223427.46 करोड़ रुपए था।

बॉश का मुनाफा पहली तिमाही में 42प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली 10 अगस्त (ए)। वाहन कलपुर्जे बनाने वाली दिग्गज बॉश लिमिटेड का शुद्ध मुनाफा 30 जून को समाप्त तिमाही में 42.42 प्रतिशत उछल कर 430.98 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में लाभ 302.61 करोड़ रुपए था। कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि आलोच्य तिमाही में उसकी परिचालन से आय 3,212.15 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2,830.44 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने कहा कि एक जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने से 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही में परिचालन से आय की तुलना पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के आंकड़े से नहीं जा सकती है। कंपनी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष

की पहली तिमाही में घरेलू बिक्री में 21.7 प्रतिशत और निर्यात में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उसका वाहन समाधान (मोबिलिटी सॉल्यूशंस) कारोबार 20.5 प्रतिशत बढ़ा है। ऊर्जा और बिजली उपकरण समेत अन्य कारोबारी क्षेत्र में 48.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान, उसका कुल खर्च 2498.16 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,677.89 करोड़ रुपए हो गया है। बॉश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सौमित्र भट्टाचार्य ने कहा कि इस वर्ष वाहन उद्योग में कंपनी ने घरेलू और वैश्विक स्तर दोनों में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना होगा महंगा, 40 प्रतिशत तक बढ़ेंगे टिकट के दाम!

नई दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। अगर आप अक्सर मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाते रहते हैं तो जल्द ही आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। मल्टीप्लेक्स में अगर खाने-पीने का सामान ले जाने की इजाजत मिल जाती है तो आपको पहले के मुकाबले 20-40 फीसदी तक अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। मल्टीप्लेक्स में फूड व बेवरेज ले जाने की इजाजत को लेकर बाम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।

रेवन्यू में आएगी कमी:खबरों के मुताबिक अगर फूड व बेवरेज को मल्टीप्लेक्स में ले जाने की इजाजत मिल जाती है तो मल्टीप्लेक्स को फूड व बेवरेज के कारोबार से मिलने वाले रेवन्यू में कमी आएगी, जिसकी भरपाई मल्टीप्लेक्स वाले निश्चित रूप से टिकट के दाम बढ़ाकर करेंगे। यानी कि अभी अगर सिनेमा के टिकट के लिए आप 200 रुपए चुकाते हैं तो आपको 240-280 रुपए तक देने पड़ सकते हैं।

सभी दर्शकों के चुकानी होगी ज्यादा कीमत:पीवीआर जैसे बड़े मल्टीप्लेक्स के कुल कारोबार में फूड व बेवरेज की हिस्सेदारी 30 फीसदी से अधिक है। चालू वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में पीवीआर ने 684.36 करोड़ रुपए का कारोबार किया और इनमें फूड एवं बेवरेज की हिस्सेदारी 202.71करोड़ रुपए की थी।

सूत्रों के अनुसार कई ऐसे दर्शक होते हैं तो मल्टीप्लेक्स में फूड व बेवरेज के महंगे होने की वजह से सिर्फ सिनेमा देखते है, कुछ खाते-पीते नहीं है। लेकिन अगर फूड व बेवरेज ले जाने की इजाजत मिलती है तो निश्चित रूप से टिकट के दाम बढेंगे जिसकी कीमत सभी दर्शकों को चुकानी होगी।

जुलाई में 8प्रतिशत बढ़ी वाहन बिक्री, कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में 30प्रतिशत का उछाल

नई दिल्ली, 10 अगस्त (ए)। घरेलू पैसेंजर वाहनों की बिक्री में 2.71 फीसद की गिरावट देखी गई है। जुलाई महीने में कार कंपनियों ने 2,90,960 यूनिट्स की बिक्री की है, जबकि जुलाई 2017 में यह आंकड़ा 2,99,066 कारों का रहा था। यह जानकारी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने दी है। टू व्हीलर्स और कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में हुई जोरदार बढ़ोतरी की वजह से जुलाई में कुल वाहन बिक्री में 8 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है।

हर 1.19 सेकेंड में बिकी 1 गाड़ी:सियाम के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के दौरान देश में कुल वाहन बिक्री 22,44,875 गाड़ियों की रही है जबकि पिछले साल जुलाई में 20,79,204 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई थी। कुल वाहन

बिक्री में सबसे अधिक हिस्सेदारी टू व्हीलर्स और पैसेंजर वाहनों की होती है। जुलाई के बिक्री आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि हर 1.19 सेकेंड में देश में 1 गाड़ी बिकी है।

टू व्हीलर्स की सेल में जोरदार बढ़ोतरी:सियाम के मुताबिक जुलाई में टू व्हीलर्स की बिक्री में 8 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, घरेलू मार्केट में कुल 18,17,077 टू व्हीलर्स बिके हैं जबकि पिछले साल जुलाई में यह आंकड़ा 16,79,876 टू व्हीलर्स का था। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में टू-व्हीलर्स के एक्सपोर्ट में 30 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, कुल 2,78,633 टू व्हीलर्स का एक्सपोर्ट हुआ है जबकि पिछले साल इस दौरान 2,13,591 टू व्हीलर्स का एक्सपोर्ट हुआ था।

कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में इजाफा:कमर्शिलय गाड़ियों की बात करें तो SIAM के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के दौरान घरेलू मार्केट में कुल 76497 कमर्शियल गाड़ियां बिकी हैं जो पिछले साल जुलाई में हुई बिक्री से लगभग 30 प्रतिशत अधिक है, पिछले साल जुलाई में 59001 कमर्शियल गाड़ियां घरेलू मार्केट में बिकी थी।

थ्री व्हीलर्स की सेल में उछाल:सियाम थ्री व्हीलर्स की बिक्री के आंकड़े भी जारी करता है और संगठन के मुताबिक जुलाई के दौरान देश में थ्री व्हीलर्स की बिक्री 46 प्रतिशत बढ़कर 60,341 गाड़ियां दर्ज की गई है। इनमें 50,232 थ्री व्हीलर्स पैसेंजर सेग्मेंट में बिके हैं और 10,109 की बिक्री गुड्स करियर के तौर पर हुई है।